राजस्थान में शहरी–ग्रामीण साक्षरता प्रारूप और भिन्नता का एक अध्ययनः एक जिला स्तरीय विश्लेषण

*डॉ. सत्यवीर यादव
**बाबूलाल शर्मा

शोध सारांश

वर्तमान शोध पत्र 1951 से 2011 तक राजस्थान और भारत दोनों में शहरी-ग्रामीण साक्षरता दर के रुझान और उनके अंतर का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। इस शोध पत्र का उद्देश्य जिले में साक्षरता दर के क्षेत्रीय प्रारूप का विश्लेषण करना भी है। यह शोध पत्र 2011 की जनगणना के आधार पर अनुमान जिला स्तर पर साक्षरता दर में शहरी-ग्रामीण अंतर के स्थानिक प्रारूप और विकास के स्तर का आकलन करने के लिए चौबीस अन्य स्वतंत्र चर के साथ इसके संबंध का भी अध्ययन करता है। राजस्थान राज्य में साक्षरता दर में शहरी ग्रामीण अंतर 1951 से 2011 तक कम होता हुआ पाया गया है। जिला स्तर पर यह देखा गया है कि पश्चिमी और दक्षिणी जिले कम विकसित आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के कारण बहुत उच्च शहरी ग्रामीण अंतर सूचकांक दर्शाते हैं। जबकि राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में शहरी ग्रामीण अंतर सूचकांक कम पाए गए हैं। अध्ययन से पता चलता है कि चौबीस चर में से ग्यारह शहरी ग्रामीण अंतर सूचकांक के साथ अपने संबंधों में 99% आत्मविश्वास के स्तर पर महत्वपूर्ण हैं, जबकि अन्य पांच चर 95% आत्मविश्वास के स्तर पर महत्वपूर्ण रूप से सहसंबद्ध हैं।

मुख्य शब्दः साक्षरता दर, राजस्थान, ग्रामीण साक्षरता, शहरी साक्षरता, साक्षरता अंतर

परिचय

सबसे बड़ी और सबसे कठिन समस्या, जिसका आज भारत जैसे विकासशील देशों के लोग सामना कर रहे हैं, वह साक्षरता की कमी का होना है, क्योंकि भारत और अन्य विकासशील देशों में साक्षरता दर का स्तर निम्न है। साक्षरता को एक मानव अधिकार माना गया है, जो सामाजिक-आर्थिक विकास और अंततः मानव समाज की सांस्कृतिक प्रगति की ओर ले जाता है। साक्षरता को व्यक्ति के सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण के रूप में भी माना जा सकता है और इसे मानव विकास सूचकांक का एक महत्वपूर्ण घटक भी माना जाता है, यह समाज के आधुनिकीकरण की

प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, जो अंततः समग्र संस्कृति में बदलाव लाएगा। साक्षरता समाज में बंधन विकसित करने में मदद करती है और गरीबी को कम करती है, जिससे अंततः लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। साक्षरता एक अच्छे सामाजिक और अच्छे सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में उत्प्रेरक की तरह काम करती है। उच्च साक्षरता दर वाला समाज हमेशा कम साक्षरता दर वाले समाज से बेहतर स्थिति में होता है। साक्षरता मानव विकास सूचकांक का मुख्य घटक होने के कारण इसका सीधा प्रभाव प्रतिव्यक्ति आय, जीवन स्तर और यहां तक कि जीवन प्रत्याशा पर पड़ता है। उच्च साक्षरता दर किसी भी क्षेत्र के विकास की गति को तेज़ कर देती है, क्योंकि विकास और साक्षरता दर में सकारात्मक संबंध होता है। साक्षरता का लोगों के दृष्टिकोण पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, लिंग अनुपात और यहां तक कि लोगों की गतिशीलता को भी प्रभावित करती है, क्योंकि साक्षर निरक्षरों की तुलना में अधिक गतिशील होते हैं। यह केवल इस तथ्य के कारण है कि साक्षरता लोगों को सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। साक्षरता समाज के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित करती है, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक चेतना और साथ ही गरीबी से ग्रस्त समाज।

समय के साथ साक्षरता की परिभाषा बदल गई है, लेकिन अब, भारत के जनगणना आयोग के अनुसार, साक्षरता को किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। हमारे देश में सात साल से कम उम्र के बच्चों को अशिक्षित माना जाता है। जबकि, यूनेस्को ने साक्षरता को विभिन्न अनुबंधों से जुड़ी मुद्रित और लिखित सामग्री को पहचानने, समझने, व्याख्या करने, बनाने, गणना करने और उपयोग करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। भारत की जनगणना के अनुसार, 1961, 1971 और 1981 की जनगणना में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निरक्षर माना गया था। 1946 से, यूनेस्को साक्षर विश्व की दृष्टि को आगे बढ़ाने और साक्षरता कौशल प्राप्त करने और सुधारने में सबसे आगे रहा है। इसे शिक्षा के अधिकार का एक हिस्सा माना गया है, जो लोगों के सशक्तिकरण, समाज के सुधार में लोगों की भागीदारी के साथ-साथ बेहतर आजीविका में योगदान की ओर ले जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों की विशेषता न केवल कम साक्षरता दर है, बल्कि ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर, पुरुष और महिला साक्षरता दर और यहां तक कि युवा और वृद्धों के बीच भी असमानताएं हैं, साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर भी असमानताएं हैं। देश में साक्षरता अंतर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू साक्षरता दर में शहरी-ग्रामीण अंतर से संबंधित है। यह इतना व्यापक है कि यह कुल जनसंख्या के साथ-साथ पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर और सभी सामाजिक जीवन में अलग-अलग परिमाण में मौजूद है। लेकिन

हमारे समाज में साक्षरता संक्रमण की शुरुआत के साथ, देश के साथ-साथ राजस्थान राज्य में भी साक्षरता दर में शहरी-ग्रामीण अंतर लगातार कम हो रहा है, और यह सुझाव दिया जा सकता है कि साक्षरता दर में परिवर्तन बहुत करीब आ रहा है। शहरी-ग्रामीण साक्षरता दर में अंतर भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में तीव्र अंतर के कारण है। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था औपचारिक शिक्षा और कौशल को उचित रूप से समर्थन नहीं देती है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि पर निर्भर करती है, जबकि शहरी अर्थव्यवस्था काफी हद तक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र पर निर्भर करती है, जिसके लिए आवश्यक रूप से न्यूनतम स्तर की साक्षरता की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं के स्तर में उल्लेखनीय भिन्नता है। साथ ही अच्छी नौकरियों और सुख-सुविधाओं की तलाश में साक्षर लोगों का ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर लगातार पलायन हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर का स्तर भी कम हो गया है। इसलिए साक्षरता दर में शहरी और ग्रामीण अंतर है।

राजस्थान की जनसंख्या 68548437 है, जो देश की जनसंख्या का लगभग 5.66 प्रतिशत है और भारत के 8वें सबसे अधिक आबादी वाले राज्य का दर्जा रखता है। 2001-2011 के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर 21.31 प्रतिशत थी, जबकि पिछले दशक में यह 28.33 प्रतिशत थी। जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, जो राष्ट्रीय औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से काफी कम है। जबकि, राजस्थान में प्रति हजार पुरुषों पर 928 महिलाओं का लिंगानुपात दर्ज किया गया।

जहां तक राजस्थान की साक्षरता दर का सवाल है, जनगणना वर्ष 2011 में यह 67.06 प्रतिशत है। कुल पुरुष जनसंख्या 35550997 में से 79.2 प्रतिशत साक्षर हैं, जबकि कुल 32997440 महिला जनसंख्या में से 52.12 प्रतिशत साक्षर हैं। राजस्थान में शहरी क्षेत्र की औसत साक्षरता दर 79.68 प्रतिशत है, जिसमें 87.91 प्रतिशत पुरुष और 63.81 प्रतिशत महिलाएँ हैं; जबकि ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर 61.44 प्रतिशत है।

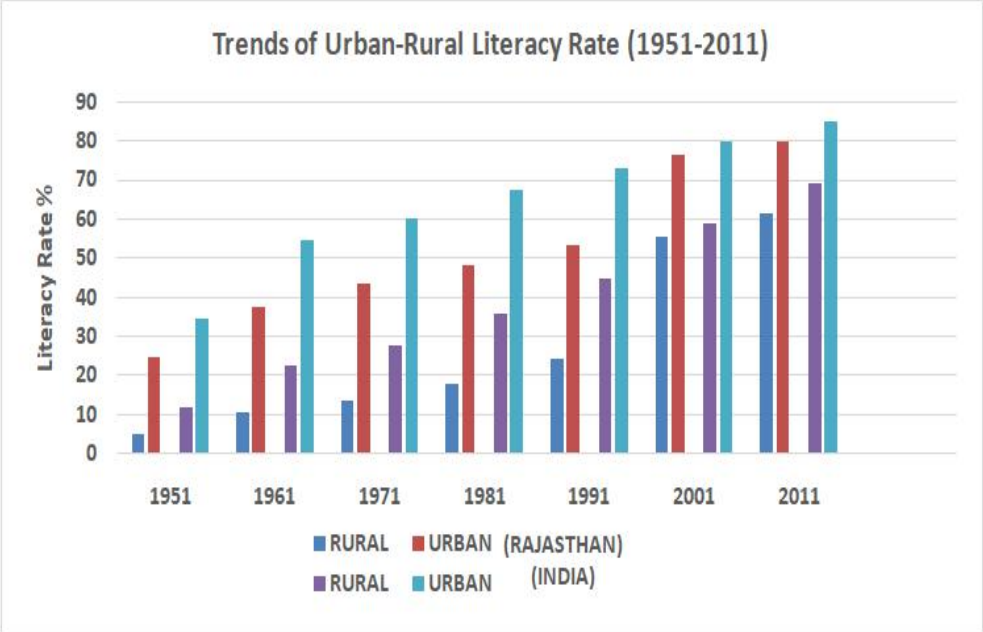

साक्षरता दर में शहरी-ग्रामीण अंतर के रुझान (1951-2011)

जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था, इसलिए निवास के आधार पर साक्षरता दर में अंतर 1951 से संभव होगा। इस तथ्य के कारण ही साक्षरता दर में शहरी-ग्रामीण अंतर की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है। 1951 से पूरे देश के साथ राजस्थान का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। 1951 से 2011 तक, राज्य के साथ-साथ पूरे देश में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर में व्यापक अंतर है।

राजस्थान में प्रतिशत, जबकि पूरे देश में 6.2 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्ज की गई। जनगणना वर्ष 2001 में 29.62 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि 1961 से 2011 के बाद से राजस्थान में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि है, जबकि पूरे भारत में उसी जनगणना वर्ष में केवल 12.64 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि बहुत कम है। राजस्थान में साक्षरता दर में वृद्धि 1961 से साक्षरता दर में लगातार वृद्धि के बावजूद, राजस्थान में 2011 में साक्षरता दर 66.11 प्रतिशत दर्ज की गई, जो भारत की औसत साक्षरता दर (74.04 प्रतिशत) से 7.93 प्रतिशत कम है।

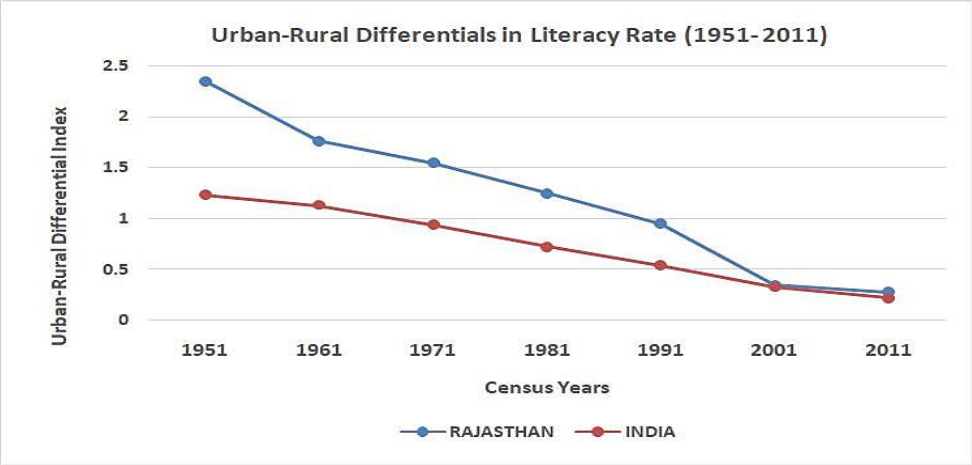

यदि हम राजस्थान के शहरी क्षेत्रों की साक्षरता दर पर नजर डालें तो पाते हैं कि 1951 में यह केवल 24.68 प्रतिशत थी, जबकि राष्ट्रीय औसत शहरी साक्षरता दर 34.6 प्रतिशत थी, जो राजस्थान राज्य से 9.92 अधिक है। राजस्थान में जनगणना समय के साथ सिमटता जा रहा है। तालिका 1 से पता चलता है कि राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 18.3 प्रतिशत की तुलना में 1951 में राजस्थान की साक्षरता दर केवल 8.38 प्रतिशत थी। जनगणना वर्ष 1961 में पूरे देश में 28.3 प्रतिशत की तुलना में 1951 में 8.38 से बढ़कर 1961 में 15.21 प्रतिशत हो गई, जो 13.09 प्रतिशत कम है। 1961 के बाद से राजस्थान के साथ-साथ पूरे भारत की साक्षरता दर में लगातार वृद्धि हुई है, जनगणना वर्ष 1971 में 3.86 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्ज की गई, साक्षरता दर 19.07 थी।

वर्ष 1961 में साक्षरता दर 37.61 प्रतिशत दर्ज की गई, जो पूरे भारत की औसत शहरी साक्षरता दर से 16.79 प्रतिशत कम है। 1971 में, राजस्थान की शहरी साक्षरता दर बढ़कर 43.47 प्रतिशत हो गई जो अभी भी 16.75 प्रतिशत अंक है, जो लगभग पिछले दशक के समान है, जो भारत की राष्ट्रीय औसत शहरी साक्षरता दर (60.22 प्रतिशत) से कम है। राजस्थान में शहरी साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि 2001 की जनगणना में 22.85 प्रतिशत अंक की वृद्धि के साथ देखी गई, जबकि पूरे भारत में उसी जनगणना में केवल 6.84 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि साक्षरता दर 79.92 प्रतिशत थी। जो राजस्थान की विकास दर से काफी कम है. जनगणना वर्ष 2011 में राजस्थान में शहरी साक्षरता दर 79.68 प्रतिशत दर्ज की गई, जो भारत की शहरी साक्षरता दर (84.98 प्रतिशत) से 11.9 प्रतिशत कम है।

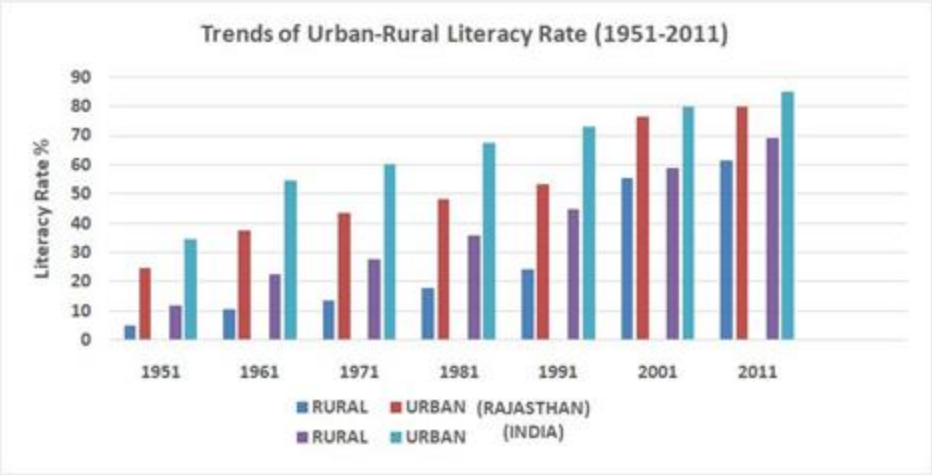

जनगणना वर्ष 1971 में राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता दर 13.85 प्रतिशत दर्ज की गई, जो कि जनगणना वर्ष 1961 से केवल 3 प्रतिशत अंक अधिक है, जबकि, उसी जनगणना वर्ष (1971) में, पूरे भारत में ग्रामीण साक्षरता दर 27.89 प्रतिशत दर्ज की गई। जो पिछले जनगणना वर्ष की तुलना में 5.39 प्रतिशत अंक अधिक है और राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता दर में वृद्धि (3 प्रतिशत अंक) से 2.39 प्रतिशत अंक अधिक है। जनगणना वर्ष 1981 में ग्रामीण साक्षरता दर 17.99 प्रतिशत दर्ज की गई, जो 1991 में बढ़कर 24.10 प्रतिशत हो गई, लेकिन ग्रामीण साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि जनगणना वर्ष 2001 में दर्ज की गई, जिसमें 31.24 प्रतिशत अंक की वृद्धि और साक्षरता दर 55.34 प्रतिशत थी। . इसने जनगणना वर्ष 2001 में 14.05 प्रतिशत अंक की वृद्धि के साथ ग्रामीण साक्षरता दर में उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की, जो राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता दर की प्रतिशत वृद्धि (31.24 प्रतिशत अंक) का लगभग आधा है।

1949 में राजस्थान के गठन के बाद, विशाल गरीबी, ध्वस्त अर्थव्यवस्था, निम्न स्तर के रोजगार, निम्न स्तर के कारण राजस्थान में साक्षरता बढ़ाना एक बहुत कठिन कार्य था।

संपूर्ण भारत और राजस्थान दोनों में साक्षरता दर में शहरी-ग्रामीण अंतर सूचकांक में गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा रही है। जनगणना वर्ष 1951 में राजस्थान में शहरी ग्रामीण अंतर सूचकांक 2.35 प्रतिशत अंक दर्ज किया गया, जबकि पूरे भारत में शहरी ग्रामीण अंतर सूचकांक केवल 1.23 प्रतिशत अंक दर्ज किया गया। जनगणना वर्ष 1961 में राजस्थान में शहरी-ग्रामीण अंतर सूचकांक में 1.76 प्रतिशत अंक की तीव्र गिरावट दर्ज की गई, लेकिन यह समग्र रूप से भारत के शहरी-ग्रामीण

अंतर सूचकांक (1.13 प्रतिशत बिंदु) से अधिक है। 1961 के बाद से शहरी-ग्रामीण अंतर सूचकांक में लगातार गिरावट आ रही है। 1971 में यह घटकर 1.55 प्रतिशत अंक और 1981 में यह घटकर 1.25 प्रतिशत अंक रह गया। 1981 के बाद, अंतर सूचकांक राजस्थान में एक सकारात्मक परिदृश्य को दर्शाता है क्योंकि 1991 में 1981 में 1.25 प्रतिशत अंक से 1991 में 0.95 प्रतिशत अंक, 2001 में 0.35 प्रतिशत अंक और 2011 में केवल 0.28 प्रतिशत अंक की तेज गिरावट दर्ज की गई। भारत में शहरी ग्रामीण अंतर सूचकांक यह 1961 से 2011 तक के सकारात्मक परिदृश्य को भी दर्शाता है। शहरी-ग्रामीण अंतर सूचकांक में तेज गिरावट दर्ज की गई, जो 1961 में 1.13 प्रतिशत अंक से 1971 में 0.94 प्रतिशत अंक हो गया, और 1981 में 0.72, 1991 में 0.54, 2001 में 0.33 और 2011 में 0.22 हो गया, जो शहरी से 0.06 अंक कम है। -राजस्थान का ग्रामीण विभेदक सूचकांक। राजस्थान और पूरे भारत में शहरी-ग्रामीण अंतर सूचकांक में यह तीव्र गिरावट दर्शाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग धीरे-धीरे उत्पादकता के साथ-साथ लघु कुटीर उद्योगों जैसे उद्योग का प्रारंभिक चरण। समाज के कमजोर वर्ग के बीच साक्षरता और शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना भी बहुत कठिन था। इसलिए, सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम), संपूर्ण साक्षरता अभियान (टीएलसी) जैसी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के गठन और कार्यान्वयन के माध्यम से राजस्थान के साथ-साथ पूरे देश में साक्षरता स्तर को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए। , सर्व शिक्षा अभियान और ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड इत्यादि, इसलिए, 1951 से 2011 तक समग्र साक्षरता दर में सुधार हुआ है। हालांकि, यह एक सर्वविदित तथ्य है कि साक्षरता दर में सुधार मुख्य रूप से राजस्थान के शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित रहा है। व्यापक अंतर के साथ शहरी क्षेत्र से पिछड़ गया। यहां उल्लेख करना महत्वपूर्ण है, और यह एक उत्साहजनक तथ्य भी है कि जनगणना वर्ष 2001 में शहरी साक्षरता दर (22.85) की तुलना में पिछले जनगणना वर्ष (1991) की तुलना में ग्रामीण साक्षरता दर (31.24 प्रतिशत अंक) में उच्च वृद्धि दर्ज की गई। प्रतिशत बिंदु) जो 8.39 प्रतिशत बिंदु का अंतर दर्शाता है।

शिक्षा के प्रति जागरूक, जिसका श्रेय इस तथ्य को दिया जा सकता है कि संचार सुविधाओं के विकास के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच संपर्क कई गुना बढ़ गया है। शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के इस संपर्क से सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार हुआ, जिससे अंततः लोगों को शिक्षा के मूल्य को समझने में मदद मिली, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी नए स्कूल और कॉलेज खोले गऐ।

शहरी-ग्रामीण साक्षरता दर का प्रारूप

कोई भी अर्थव्यवस्था चाहे वह विकसित हो या विकासशील, आर्थिक वृद्धि और मानव विकास में

शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। मानव समाज तभी प्रगति कर सकता है जब मानव संसाधनों का उपयोग उसके पूर्ण रूप में किया जा सके। राजस्थान राज्य में, 2001 की जनगणना रिपोर्ट में साक्षरता दर में शानदार सुधार हुआ है। 2001 की जनगणना से पता चलता है कि राजस्थान ने 60.41 प्रतिशत की साक्षरता दर के साथ भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की है, जो कि है पिछले दशक 1991 की तुलना में 29.62 प्रतिशत अंक अधिक है। यदि हम 2001 में राजस्थान की साक्षरता दर की तुलना भारत की साक्षरता दर से करते हैं, तो हम पाते हैं कि भारत में साक्षरता दर 64.84 प्रतिशत दर्ज की गई, जो कि राजस्थान से 4.43 प्रतिशत अंक अधिक है। पिछले जनगणना वर्ष से केवल 12.64 प्रतिशत अंक की वृद्धि राजस्थान में (29.62 प्रतिशत अंक)। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर 66.11 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो कि जनगणना वर्ष 2001 की तुलना में केवल 5.7 प्रतिशत अधिक है, और भारत की साक्षरता दर (74.04 प्रतिशत) से भी काफी कम है। झुंझुनू (74.1), अलवर (70.7), भरतपुर (70.1), जयपुर (75.5), सीकर (71.9) और कोटा में साक्षरता दर शानदार रही है।

शहरी और ग्रामीण साक्षरता दर का क्षेत्रीय प्रारूप सभी स्तरों पर भिन्नता दर्शाता है। यदि हम 2011 में ग्रामीण साक्षरता दर पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि सबसे अधिक ग्रामीण साक्षरता दर

झुंझुनू में दर्ज की गई है, ग्रामीण साक्षरता दर 73.4 प्रतिशत है, जिसके बाद सीकर (70.8), कोटा (68.6) और धौलपुर (68.1) का स्थान है। जबकि सबसे कम साक्षरता दर 49 प्रतिशत के साथ सिरोही जिले में देखी गई है, जो राज्य की औसत ग्रामीण साक्षरता दर (61.4) से 12.4 प्रतिशत कम है। 2011 में ग्रामीण साक्षरता दर के संदर्भ में जिलों को पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, निम्न (50 प्रतिशत से नीचे), मध्यम (50.01 से 60 प्रतिशत), उच्च (60.01 से 70 प्रतिशत), और बहुत उच्च (70 प्रतिशत से ऊपर)। ग्रामीण साक्षरता दर से संबंधित आंकड़ों से पता चलता है कि, राजस्थान के 33 जिलों में से केवल एक जिला है, जिसका नाम सिरोही (49 प्रतिशत) है, जिसे ग्रामीण साक्षरता दर के निम्न स्तर के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, जो राज्य के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित है और बनता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का केवल 1.50 प्रतिशत, जबकि सत्रह जिले, जिनके नाम हैं, बीकानेर (58.1), जोधपुर (58.5), पाली (58.4), अजमेर (59.1), टोंक (58), बूंदी (57.3), जैसलमेर (53.8) ,बाड़मेर (54.8), जालोर (53.3), भीलवाड़ा (56), राजसमंद (59.5) डूंगरपुर (57.61), बांसवाड़ा (54), चित्तौड़गढ़ (56.8), झालावाड़ (57.6), उदयपुर (54.9) और प्रतापगढ़ (53.2) हैं ग्रामीण साक्षरता दर के मध्यम स्तर के अंतर्गत वर्गीकृत। इन सत्रह जिलों में से, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित हैं। ये सभी सत्रह जिले, जिन्हें ग्रामीण साक्षरता दर के मध्यम स्तर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 63.69 प्रतिशत है। उपर्युक्त अठारह जिलों के अलावा, तेरह जिले हैं, जिनके नाम हैं, गंगानगर (66.2), हनुमानगढ़ (65.1), चूरू (64.4), अलवर (67.9), भरतपुर (67.9), धौलपुर (68.1), करौली (65) , सवाई माधोपुर (61.9), दौसा (66.3), जयपुर (67.6), नागौर (60.9), कोटा (68.6) और बारां (63.6), जिसे उच्च स्तर की साक्षरता के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है और यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30.82 प्रतिशत है। राजस्थान में, जबकि केवल दो जिले हैं, जिनका नाम झुंझुनू और सीकर है, जिन्हें 70 प्रतिशत से ऊपर की साक्षरता दर के बहुत उच्च स्तर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और जो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 3.99 प्रतिशत है। चौदह जिले हैं जिनके नाम हैं, गंगानगर (78.70), हनुमानगढ़ (75.40), बीकानेर (78.00), झुंझुनू (76.50), भरतपुर (79.00), सवाई माधोपुर (79.00), सीकर (75.40), जोधपुर (79.40), जैसलमेर (78.00), बाड़मेर (78.20), सिरोही (78.70), पाली (75.80), बूंदी (77.90) और बारां (78.00) को शहरी साक्षरता दर के मध्यम स्तर के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है और यह राजस्थान के एक प्रमुख क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 56.69 प्रतिशत शामिल है। ऐसे ग्यारह जिले हैं जिन्हें उच्च स्तर की शहरी साक्षरता दर (80.01 से 85 प्रतिशत) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनके नाम अलवर (83.40), दौसा (80.70), जयपुर (82.50), अजमेर (83.90), भीलवाड़ा (80.70), राजसमंद हैं।

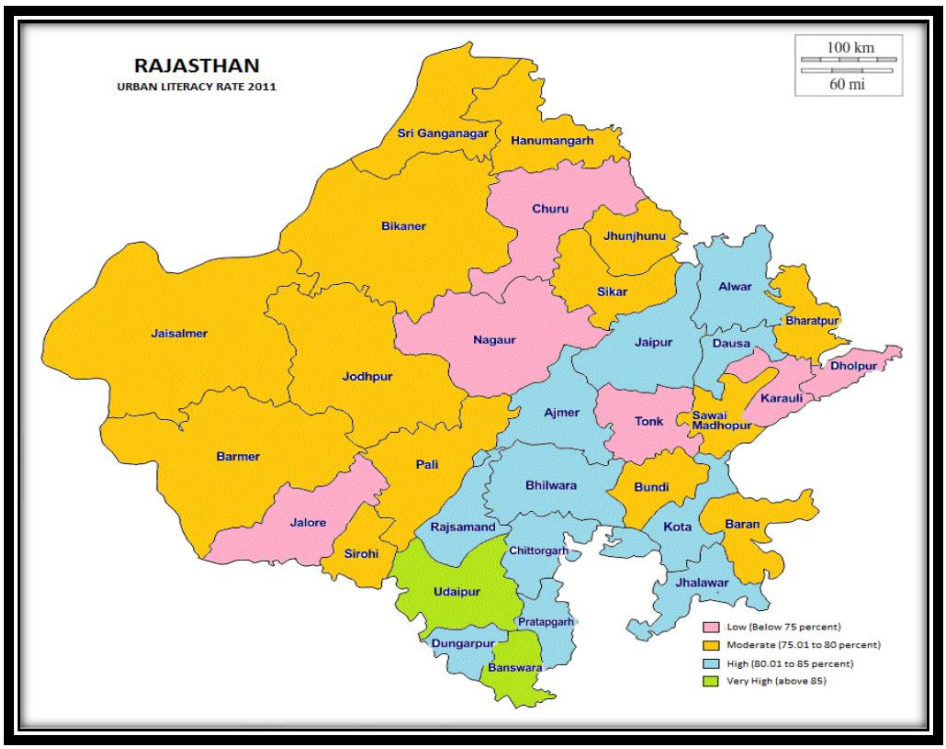

(81.90), डूंगरपुर (84.40), चित्तौड़गढ़ (82.70), कोटा (81.70), झालावाड़ (81.10) और प्रतापगढ़ (84.80)। इसलिए, राजस्थान के एक बड़े हिस्से को उच्च स्तर की साक्षरता दर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और यह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का 21.63 प्रतिशत है। शहरी साक्षरता दर के उच्च स्तर के अंतर्गत वर्गीकृत अधिकांश जिले पूर्वी जिले हैं। राजस्थान के 33 जिलों में से केवल दो जिले, जिनका नाम बांसवाड़ा (85.20) और उदयपुर (87.50) है, को बहुत उच्च स्तर की साक्षरता दर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ये दोनों जिले राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित हैं और राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 4.75 प्रतिशत हिस्सा हैं।

शहरी-ग्रामीण अंतर

यह पहले ही देखा जा चुका है कि राजस्थान में ग्रामीण-शहरी साक्षरता दर के बीच व्यापक अंतर है; लेकिन 1951 से 2011 तक राज्य स्तरीय शहरी-ग्रामीण अंतर सूचकांक स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि, यह 1951 में 2.35 प्रतिशत बिंदु से लगातार कम होकर 2011 में 0.28 प्रतिशत बिंदु

पर आ गया है। यदि हम साक्षरता दर में शहरी-ग्रामीण विभिन्न सूचकांक पर गौर करें जिला स्तर पर, हम पाते हैं कि राजस्थान के सभी 33 जिलों के बीच अंतर सूचकांक में उल्लेखनीय भिन्नता है। शहरी-ग्रामीण विभेदक सूचकांक प्रतापगढ़ में 0.56 से लेकर झुंझुनू में 0.04 तक है, राज्य का औसत है।

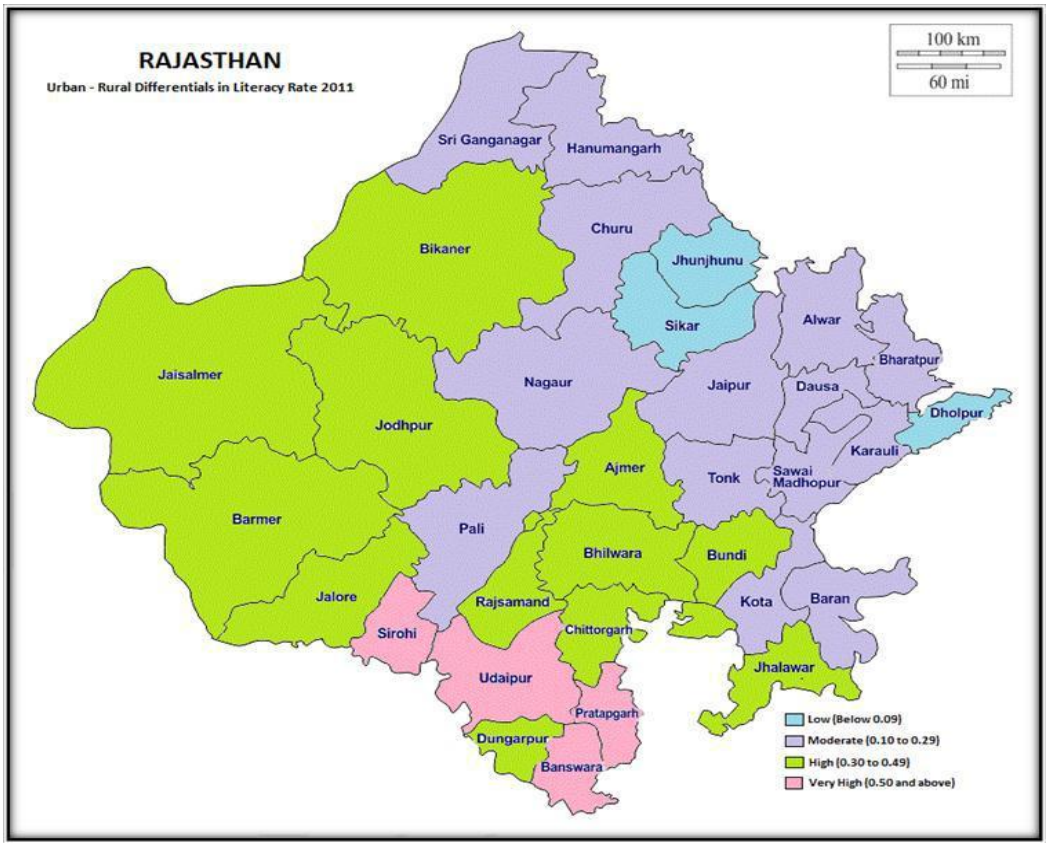

राजस्थान के 33 जिलों में से 16 में शहरी-ग्रामीण अंतर सूचकांक राज्य के औसत 0.28 से अधिक दर्ज किया गया। इसका मतलब है कि राजस्थान के लगभग आधे जिलों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर के बीच व्यापक अंतर है, हालांकि समय के साथ यह कम हो रहा है। शहरी-ग्रामीण साक्षरता दर के स्थानिक पैटर्न को समझने के लिए राजस्थान के सभी 33 जिलों को शहरी ग्रामीण अंतर सूचकांक के आधार पर आसानी से चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है। राजस्थान के जिलों

को निम्न (0.09 से नीचे), मध्यम (0.10 से 0.29), उच्च (0.30 से 0.49) और बहुत उच्च (0.50 और अधिक) में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस वर्गीकरण के आधार पर हम झुंझुनू (0.04), धौलपुर (0.07) और सीकर (0.06) नामक तीन जिलों को शहरी ग्रामीण अंतर सूचकांक के निम्न स्तर के तहत वर्गीकृत कर सकते हैं, और राज्य के औसत शहरी ग्रामीण अंतर सूचकांक 0.28 से काफी नीचे हैं। . झुंझुनू और सीकर राज्य के उत्तरी भाग में स्थित हैं, जबकि धौलपुर राज्य के पूर्वी हिस्से में स्थित है और उनकी सीमा उत्तर पूर्व में हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगती है। 0.09 से नीचे निम्न शहरी-ग्रामीण अंतर सूचकांक दर्शाता है कि इन तीन जिलों में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। शहरी और ग्रामीण साक्षरता दर में इस कमी का श्रेय इस तथ्य को दिया जा सकता है कि, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से निकटता के कारण, इन जिलों में ग्रामीण लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हो गए हैं और शिक्षा के लाभों के बारे में अधिक जागरूक हो गए हैं। इसके अलावा सरकार ने राज्य के साथ-साथ पूरे देश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। राजस्थान के 33 जिलों में से चौदह जिले, जिनके नाम गंगानगर (0.18), हनुमानगढ़ (0.15), चूरू (0.12), अलवर (0.22), भरतपुर (0.16), करौली (0.12), सवाई माधोपुर (0.26), दौसा (0.21), जयपुर (0.20), नागौर (0.15), पाली (0.28), टोंक (0.26), कोटा (0.17) और बारां (0.22) 0.10 से 0.29 के बीच मध्यम शहरी-ग्रामीण अंतर सूचकांक के अंतर्गत आते हैं। इन चौदह जिलों में से एक जिला, जिसका नाम पाली है।

संबंध विश्लेषण

सभी चौबीस स्वतंत्र चरों के बीच संबंध का पता लगाने और उनकी एक-दूसरे से तुलना करने के लिए सहसंबंध मैट्रिक्स तैयार किया गया है, साथ ही शहरी-ग्रामीण अंतर सूचकांक और प्रत्येक स्वतंत्र चर के बीच सहसंबंध का एक सरल गुणांक 99 पर गणना और परीक्षण किया गया है। 95% आत्मविश्वास का स्तर, इस धारणा के साथ कि सभी मामलों में सहसंबंध मौजूद है।

साक्षरता दर में शहरी-ग्रामीण अंतर और अन्य स्वतंत्र चर के बीच सहसंबंध का पता लगाने के लिए कार्ल पियर्सन की गुणांक सहसंबंध की विधि को अपनाया गया है। दो चर तब सहसंबद्ध माने जाते हैं जब एक में वृद्धि या कमी दूसरे में वृद्धि या कमी से मेल खाती है। चौबीस चर में से ग्यारह, साक्षरता दर में शहरी-ग्रामीण अंतर सूचकांक के साथ उनके संबंध में विश्वास के 99 प्रतिशत स्तर पर महत्वपूर्ण हैं। इस ग्यारह चर में से केवल चार चर, जिन्हें लिंग अनुपात (आर = 0.47), शहरी साक्षरता दर (आर = 0.63), एस.टी. नाम दिया गया है। जनसंख्या का कुल जनसंख्या से (r= 0.65), कुल श्रमिकों का कुल जनसंख्या से (r= 0.54) का साक्षरता दर में शहरी-ग्रामीण अंतर के साथ सकारात्मक संबंध है। ये चार चर शहरी-ग्रामीण अंतर सूचकांक (सकारात्मक सहसंबंध का मध्यम

स्तर +0.25 से +0.75) के साथ सकारात्मक सहसंबंध का एक मध्यम स्तर दर्शाते हैं। इन चार चर के अलावा बाकी सात चर को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय वाले गांव (आर = -0.53), कुल साक्षरता दर (आर = -0.78), ग्रामीण साक्षरता दर (आर = -0.90), कुल पुरुष साक्षरता दर (आर) के रूप में नामित किया गया है। = -0.79), कुल महिला साक्षरता दर (आर = -0.79), कुल महिला साक्षरता दर (आर = -0.70), एस.सी. जनसंख्या (आर = -0.63) और क्रेडिट सोसायटी वाले गांव (आर = -0.46) नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध हैं। शहरी-ग्रामीण अंतर सूचकांक. इन सात चरों में से, चार संकेत देते हैं कि रिश्ते की ताकत नकारात्मक दिशा में सहसंबंध के मध्यम स्तर की है (नकारात्मक सहसंबंध का मध्यम स्तर -0.25 से -0.75), जबकि, बाकी तीन संकेत करते हैं कि रिश्ते की ताकत उच्च स्तर की है नकारात्मक दिशा में (नकारात्मक सहसंबंध का उच्च स्तर -0.75 से -1)। इन सात चरों के अलावा, जो 99% आत्मविश्वास के स्तर पर महत्वपूर्ण हैं, पाँच चर हैं, जो महत्वपूर्ण हैं।

साक्षरता दर में शहरी-ग्रामीण अंतर सूचकांक के साथ उनके संबंधों में 95% के स्तर पर विश्वास है। इन पांच चरों में से, केवल दो चर, जिन्हें ग्रामीण जनसंख्या से कुल (आर = 0.35), कृषि मजदूरों से कुल श्रमिकों (आर = 0.41) के रूप में नामित किया गया है, सकारात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और सहसंबंध की ताकत मध्यम स्तर (सकारात्मक सहसंबंध का मध्यम स्तर) है +0.25 से +0.75), जबकि, शेष तीन चरों के नाम हैं, मिडिल स्कूल वाले गाँव (r= -0.38), माध्यमिक स्कूल वाले गाँव (r= -0.48), शहरी जनसंख्या बनाम कुल जनसंख्या (r= - 0.35) शहरी-ग्रामीण अंतर सूचकांक के साथ नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध हैं और सहसंबंध की ताकत मध्यम स्तर की है। शेष आठ चर में से, घरेलू उद्योगों का कुल श्रमिकों से कोई संबंध नहीं है (आर = 0.00) और केवल एक चर है, जिसे नाम दिया गया है, कुल श्रमिकों (0.01) के साथ कृषक सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध हैं और संबंध की ताकत निम्न स्तर की है और शेष चर नकारात्मक दिशा में सहसंबद्ध हैं।

***प्रोफेसर**
सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेर बारी झुंझुनू
****शोधार्थी**
भूगोल विभाग
स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एण्ड एजुकेशन सिंघानिया विश्वविद्यालय
पचेर बारी झुंझुनू (राज.)

संदर्भ

1. अजीम, एस. (2005), कर्नाटक में साक्षरता वृद्धि असमानताएं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 40(16), 1647-1649।

2. अली आई, रेड्डी आर (1995)। भारत की जनसंख्या समस्या: समाजशास्त्रीय अध्ययन, भारत जे. रजि. विज्ञान., 27(1): 2.
3. चंदना, आर.सी. (2009)। पंजाब और हरियाणा में साक्षरता-2001। पंजाब भूगोलवेत्ता, 5, 116-120।
4. डिसूजा वी.एस. (1982)। ग्रामीण-शहरी असमानताएँ: शिक्षा, जनसांख्यिकीभारत, 11(2): 202-205।
5. पोपुल देव रेव. 7(1):55-70.
6. गुप्ता, एम.डी. एवं भट्ट, पी.एन.एम. 1995. भारत में तीव्र लिंग पूर्वाग्रह: प्रजनन क्षमता में गिरावट का परिणाम। जनसंख्या और विकास अध्ययन के लिए हार्वर्ड केंद्र। वर्किंग पेपर नंबर 95.02.
7. गुप्ता, एम.डी. 1987। ग्रामीण पंजाब, भारत में बच्चियों के ख़िलाफ़ चयनात्मक भेदभाव। पॉपुल. देव. प्रका0वा0 13:77-100.
8. एचावर्री, आर. ए. और एज़कुरा, आर. 2010. जन्म के समय लिंग अनुपात में शिक्षा और लिंग पूर्वाग्रह: भारत से साक्ष्य।
9. जनसांख्यिकी। 47:249-268.
10. भारत, वन राज्य रिपोर्ट। 2019 खण्ड-ii-राजस्थान। 222 पी.पी.
11. कुमार, एम. 2011. महिला साक्षरता और बाल लिंग अनुपात के बीच सहसंबंध: एक भौगोलिक विश्लेषण, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान में उन्नत अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। 2(4):65-73
12. पटेल, वी. 2002. नई सहस्राब्दी की महिलाओं की चुनौतियाँ। ज्ञान बुक्स, दिल्ली, पृष्ठ 70।
13. चंदना, आर.सी. 2008. जनसंख्या का भूगोल: अवधारणाएँ, निर्धारक और पैटर्न, कल्याणीप्रकाशक, नई दिल्ली।
14. चेन, एल.सी. हक, ई. और डिसूजा, एस. 1981. ग्रामीण बांग्लादेश में भोजन और स्वास्थ्य देखभाल के पारिवारिक आवंटन में लिंग पूर्वाग्रह।